



CHOICE OF MILLIONS®
SHERKOTTI
HARDWARE & PAINT TOOLS
www.charminarbrush.com

9440297101



SHERKOTTI
SPRAY PAINT

वर्ष-30 अंक : 132 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) श्रावण शु.13 2082 गुरुवार, 7 अगस्त-2025

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र वास्ता



epaper.vaartha.com
Vaartha Hindi
@Vaartha_Hindi
Vaartha official
www.hindi.vaartha.com

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर * पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे
एससीओ समिट में शामिल होंगे-मोदी 11 साल में 5 बार चीन जा चुके हैं
नई दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। यहां वो भारत-जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

सत्ता का नया केंद्र कर्तव्य भवन भारत पर 50% टैरिफ

* इसमें गृह-विदेश समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस * 24 कॉन्फ्रेंस रूम के साथ 600 कारों की पार्किंग सुविधा

नई दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-03 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट (सीएसएस) की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन-03 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है। इसे दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर स्थित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोआर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ग्राउंड फ्लोर सहित 7 फ्लोर हैं। यहां गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस



मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस होंगे। कर्तव्य भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है। यहां एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। इसमें क्रेच (शिशुगृह), योग रूम, मेडिकल रूम, कैफे, किचन और हॉल है। कर्तव्य भवन में 24 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। हर रूम 45 लोगों के बैठने

की क्षमता है। सरकार के अनुसार, अभी कई मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच बने शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से जरूर हो चुकी हैं। अगले महीने पूरा होगा कर्तव्य भवन-1 और 2 का काम

केंद्र ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट (सीएसएस) की शुरुआत की है। इसके तहत दस बिल्डिंग और एक एजीक्यूटिव एन्क्लेव बनाने की योजना है। इनमें कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। यह अगले महीने तक पूरी हो जाएगी। वहीं, अगले 22 महीनों में बचे हुए

7 भवन भी बन जाएंगे। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएट में एक नया प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। एजीक्यूटिव एन्क्लेव के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एरिया का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, सरकार ने नया संसद भवन और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लंद चुका

वांशिंगटन, 6 अगस्त (एजेंसियां)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एजीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एजीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल कहा था कि भारत, रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एजीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है-“भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लंद चुका



है और रास्ते में है, या यदि वह कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब ट्रम्प प्रशासन ने यह पाया कि भारत उस रूसी तेल को खरीद रहा है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। इस वजह से अब अमेरिका ने भारत पर यह नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है।’ अप्रैल 2025 में जारी एक और आदेश में कुछ खास उत्पादों को पहले ही टैरिफ से छूट दे दी गई थी वे छूट अब भी जारी रहेंगी। इन सामानों में सेमी-कंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु व खनिज शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी टैरिफ की दर बदल सकते हैं या और नए प्रावधान जोड़ सकते हैं।

सेना के 11 जवान अब भी लापता

उत्तरकाशी, 6 अगस्त (एजेंसियां)। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के बाढ़ग्रस्त धराली में भारी बारिश के बीच आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक दिन पहले अचानक आयी बाढ़ में फंसे करीब 150 को बचा लिया गया है लेकिन सेना के 11 जवान अब भी लापता हैं। उप महानिरीक्षक (संचालन) मोहसिन शाहेदी ने संवाददाताओं को बताया कि तीन टीम धराली गांव के लिए रवाना हो चुकी थीं लेकिन भूस्खलन के कारण ऋषिकेश-उत्तरकाशी राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण उसे पहुंचने में देरी हुई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मंगलवार दोपहर बाद बादल फटने से खीरगंगा नदी में आयी भीषण बाढ़ में करीब आधा गांव तबाह हो गया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, विनाशकारी बाढ़ में चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान में 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

राहुल को मिली जमानत

नई दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसियां)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में बीजेपी के एक नेता ने झारखंड में मानहानि केस दर्ज किया गया था। आज राहुल गांधी इस मामले में चार्जबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने शर्तों के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी। अमित शाह पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान टिप्पणी की थी।

ट्रम्प धमका रहे, मोदी सामना नहीं कर पा रहे : राहुल

> अडाणी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच से उनके हाथ बंधे हैं

नई दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसियां)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, ट्रम्प की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडाणी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का एए (अडाणी-अंबानी) के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अर्टोनी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक, अडाणी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी



तरीके से सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह देश के लिए खतरनाक है। ट्रम्प आज भारत पर और ज्यादा टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कल (5 अगस्त) को कहा था कि वे 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रम्प ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था।

अधिकारियों को रिश्तत दी गई थी। इसकी जांच जारी है। राहुल ने कहा-अगर पीएम मोदी में इंदिरा गांधी की तरह 50 प्रतिशत भी दम है तो कह दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। प्रधानमंत्री अपनी छवि बचाने के लिए जिस तरह से सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह देश के लिए खतरनाक है। ट्रम्प आज भारत पर और ज्यादा टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कल (5 अगस्त) को कहा था कि वे 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रम्प ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था।

बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार तक मांगी जानकारी

नई दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया है कि वह बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नाम की एनजीओ को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने बिहार में 24 जून को 'विशेष सचन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर)' शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दिखाए गए। लेकिन इसमें से 65 लाख से अधिक वोटर्स के नाम हटा दिए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि ये लोग या तो मर चुके हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गए हैं, या दो जगहों पर नाम था। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भूयान और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा, 'हमें हर उस वोटर की जानकारी चाहिए जिसका नाम हटाया गया है।



CELEBRATING
50
YEARS
ANNIVERSARY
1975 2025



World's 1st Jewellery Showroom to present more than 100 exclusive Hallmarked Dulhan set's Certified by BIS

SHIVRAJ LAXMICHAND JAIN JEWELLERS

Exclusive Traditional & Designer Jewellery Collection

EXCLUSIVE DESIGNER * GOLD * DIAMOND * POLKI * SILVER * JEWELLERY COLLECTION - 2025



WHOLESALE PRICES GUARANTEED
जहाँ विश्वास ही परम्परा है
SINCE 1975

TOMORROW LAST DAY

बदल अंतिम दिन

DIAMOND JEWELLERY

FLAT **15%** DISCOUNT
on diamonds & polki

SILVER UTENSILS

FLAT **50%** DISCOUNT
on making charges.

SILVER JEWELLERY

FLAT **20%** DISCOUNT
on silver jewellery.

GOLD EXCHANGE

OLD GOLD EXCHANGE
facility available.

GRAND monsoon SALE

FLAT **100%**

22CT JEWELLERY at Pure Gold Rate

ON COMPLETE STOCK.

NO MAKING • NO WASTAGE

SLJ JEWELLERS
जहाँ विश्वास ही परम्परा है

WORLD LARGEST BRIDAL JEWELLERY COLLECTION NOW AT SLJ.

20000+ LATEST DESIGNS
READY TO EXPLORE.

6-3-1111/2, adjacent to westside
somajiguda circle,
Hyderabad - 500016.

97 80 916 916 / 70 90 916 916
83 84 916 916 / 63 09 916 916

BIGGER * BETTER
WORLDCLASS

गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 3

मैंने राजनीति से किनारा
कर लिया है: चिरंजीवी

हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वातंत्र्य वार्ता)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय अभिनेता चिरंजीवी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने राजनीति पूरी तरह छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि भले ही वे राजनीति से दूर हैं, फिर भी कुछ नेता सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना और मलबामें उड़ाते रहते हैं। उन्होंने सनसनखेज टिप्पणी की कि वे राजनीतिक आलोचनाओं का ज़्यादा जवाब नहीं देते। चिरंजीवी हैदराबाद में फीनिक्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित रक्तदान अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक नेता ने उनके बारे में कुछ अनुचित कहा। चिरंजीवी ने कहा कि जो लोग उनके बारे में बुरा लिखते और बोलते हैं, उन्हें सबसे अच्छा जवाब वही है कि वे अच्छा काम करें। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अच्छा काम करने का मतलब अपने भाइयों के साथ सहयोग करना है, जो अच्छा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार द्वारा लिखा गए लेख को पढ़ने के बाद उन्हें ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार आया और वे हमेशा उनके कृपियों रहेंगे। चिरंजीवी का राजनीति से दूर रहने का बयान तेजगंगा की राजनीति में एक गम तैयार बन गया है। हाल ही में, चिरंजीवी ने मुख्यमंत्री खेत रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि इस बात की खूब चर्चा थी कि दोनों की मुलाकात उस अभियान के तहत हुई थी जिसके तहत खेत रेड्डी आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव में चिरंजीवी को मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले, चिरंजीवी ने अपनी प्रजा राज्यम पार्टी का कांसेस पार्टी में विलय कर दिया था और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था।

हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वाता।) तेलंगणा काग्रेस ने बुधवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल धराना दिया और राज्य में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की। यह धराना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी अध्यक्ष मोहन कुमार गौड़ के नेतृत्व में, राज्य काग्रेस नेतृत्व के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसमें तेलंगणा के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान प्राध्वद, निगम अध्यक्ष, जिला काग्रेस अध्यक्ष और विभिन्न जिलों के प्रमुख पिछड़ा वर्ग नेता शामिल हुए। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक समूहों, विशेष रूप से ईडीआ

भट्टी ने जंतर

ब्लॉक गठबंधन के नेताओं ने भी इस पहल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए धरने में भाग

लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण की वकालत करने की

अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया और कहा कि वह इस लड़ाई को सड़कों से लेकर दिल्ली तक ले

जाएँ। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा में स्वीकृत हो चुका है और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विधेयक को मंजूरी देने में राष्ट्रपति की देरी पर निराशा व्यक्त की।

रवंत रड्डो न पछड़ा वग आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मग्यो जने पर अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने पछड़ा वग आरक्षण स्थापित करने में केंद्र सरकार की तत्परता की कमी की आलोचना की और तेलंगाना की तरह पूरे देश में जाति जनगणना कराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी जाति व्यक्त की के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति को उन्हें मिलने का समय न देने की सलाह दी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पछड़ा वग आरक्षण लागू होने तक उनके प्रयास जारी रहेंगे। रवंत रड्डो ने केंद्र डिप्टी करते हुए कहा कि अगर पछड़ा वग विधेयक पारित नहीं हुआ तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर पछड़ा वग आरक्षण की स्थापना की उम्मीद करके का आरोप लगाया। वे इस बात से नाराज थे कि विधेयक को केंद्र को सौंपे हुए चार महीने बीत चुके हैं और कोई प्रगति नहीं हुई है। रवंत रड्डो ने मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के बहाने पिछड़े वर्ग के आरक्षण में बाधा डालने के लिए भाजपा की भी निंदा की।

हेराराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना और फिलीपींस ने अपने-अपने क्षेत्रों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। नगराज आपूर्ति मंत्री ए. जयम कुमार रेड्डी ने बुधवार को नई दिल्ली में फिलीपींस के कृषि मंत्री फ्रांसिस्को पी तियु लारेल् जुनियर से मुलाकात की और दोनों क्षेत्रों के बीच चावल और धान के व्यापार के विस्तार पर चर्चा की। अपनी बैठक में, फिलीपींस के मंत्री ने तेलंगाना के चावल की उच्च गुणवत्ता की सराहना की और आगामी वर्ष के लिए देश की लगभग 20 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए चावल और धान के आयात को बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने तेलंगाना से चावल और धान के निर्यात को बढ़ाने में भी रुचि व्यक्त की, विशेष रूप से तेलंगाना की सोना (आरएनआर 15048) चावल किस्म के आयात की इच्छा पर प्रकाश

झाला और मक्का के आयात की संभावनाओं पर भी विचार किया। बैठक के दौरान, उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना और फिलीपींस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता का वादा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने फिलीपींस के मंत्री को इस वर्ष के अंत में तेलंगाना आने का निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बैठक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि फिलीपींस के मंत्री ने तेलंगाना के चावल के अलावा धान के निर्यात के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फिलीपींस के कृषि मंत्री फ्रांसिस्को पी. लियु लॉरल जूनियर ने भी तेलंगाना से धान आयात करने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने यह भी बताया कि वे जल्द ही नगरािक आपूर्ति मंत्री को फिलीपींस आने का निमंत्रण देंगे। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों और सहयोग को और गहरा करने की दिशा इच्छा व्यक्त की।

मंत्री तुम्माला ने संसद में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण से मुलाकात की

नई दिल्ली, 6 अगस्त (स्वतंत्र
वार्ता)। तेलंगाना के राज्य मंत्री
गुप्तामाला, जो आज दिल्ली के
जंतर-मंतर पर पिछड़ी जातियों को
42 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग
को लेकर आयोजित धरने में
शामिल हुए थे, ने संसद में केंद्रीय
मंत्री जेपी नड्डा और मिर्लाना
सीतारामण से मुलाकात की और
राज्य को आवंटन के अनुसार
यूरीया की तत्काल आपूर्ति की
मांग की। उन्होंने यह सुनिश्चित
करने के लिए तत्काल कदम उठाने
का अनुरोध किया कि अप्रैल से
अब तक यूरीया की आपूर्ति में हुई
कमी की पूर्ति अगस्त महीने के
आवंटन के साथ ही की जाए।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा के ध्यान
में लाया कि वर्तमान में राज्य में
केवल 1.09 लाख मीट्रिक टन
यूरीया उपलब्ध है और कहा कि
आपूर्ति में देरी होने पर किसानों
को केजिन्डाइयों का सामना करना
पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि
तेल संरक्षक ने अगस्त महीने के
लिए राज्य को 1.70 लाख
मीट्रिक टन यूरीया आवंटित किया
है। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल
से जुलाई तक राज्य में 2.10
लाख मीट्रिक टन यूरीया की कमी
है और अगस्त माह के
आवंटन के साथ ही यूरीया की
आपूर्ति भी तुरंत की जानी चाहिए।

रूखी प्रकार, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण से मुन्नालाकात की ओर उनसे कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को 2018 की तरह 44 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया कि कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को 2% 5 प्रतिशत से घटाकर 16.5 प्रतिशत करने से न केवल पाम तेल की गुलती की कीमत कम होगी, बल्कि पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने में भी बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने पहले भी आयात शुल्क को 27.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत करने का अनुरोध किया था। राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि ववह वर्तमान में शुरू हो रहे खेती के मौसम के संदर्भ में इस निर्णय की एक बार फिर समीक्षा करें,

पूँज्यों और किसानों को उचित प्रोत्साहन प्रदान करें और इस प्रफल की खेती को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुनर्प्राण-औ-आपी योजना के तहत तेलंगाना राज्य देश में तेल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आयात शुल्क कम करने के केंद्र सरकार के फैसले से राज्य सरकार द्वारा आपाम आयात की खेती के विस्तार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में बाधा आ सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मंत्री निर्मला सीतारमण से कच्चे आपाम तेल पर कम किए गए आयात शुल्क को पुनः 44 प्रतिशत करने का आग्रह किया। मंत्री के साथ सांसद चमला किरण कुमार रेड्डी भी थे।

पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देख रहा है: भाजपा पायल शंकर

हेदाराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। आदिलाबाद के भाजपा विधेयक पायल शंकर ने आज कहा कि राज्य के पिछड़े वर्ग के लोग दिल्ली में 42 प्रतिशत पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कामारोड्डी घोषणापत्र को लागू करने का कोई हेदारा नहीं है। उन्होंने कहा, "हमने विधानसभा तब स्पष्ट कर दी थी जब यहानसभा में पिछड़ा वर्ग विधेयक पेश किया गया था। वे पिछड़ा वर्ग आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने के पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से बच रहे हैं। हमने तब कहा था कि विधेयक यहीं पेश किया जाएगा और भविष्य में दिल्ली में धरना दिया जाएगा। हमारी यह बात आज कांग्रेस द्वारा कि यह रहे नाटकों के रूप में सच हो रही है। कांग्रेस ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्या वे 42 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को आरक्षण देंगे, नहों विधानसभा में मुसलमानों, नहों। कांग्रेस ने अभी तक हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली में मौजूदा विरोध प्रदर्शन को 42 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए

बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में, जब मुसलमानों को 10 प्रतिशत वोट देने के इरादे से किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में जब तेलंगाना बना था, तब पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था और कहा कि 42 प्रतिशत के नाम पर आरक्षण बढ़ा दिया गया है और मुसलमानों को 10 प्रतिशत आरहित करके पिछड़े वर्गों के लिए केवल 32 प्रतिशत ही बचा है। "2014 में जो 34 प्रतिशत आरक्षण था, उसे अब घटाकर 32 प्रतिशत किया जा रहा है। आज राज्य के पिछड़े वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि यह कैसा सौदा है। कामगारों को घोषणापत्र में कहा गया था कि पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये की उप-योजना निधि आवंटित की जाएगी। दो बजट पेश होने के बाद भी एक पैसा भी जारी नहीं किया गया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री इंसुदी रेड्डी और कांग्रेस पार्टी को रोकना जवाब देना चाहिए। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग निम्नों के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते थे। तेलंगाना राज्य बनने के बाद, टीआरएस शासन में पिछड़े वर्ग के लोगों को एक दशक तक ठगा गया।"

महाप्रबंधक ने तृती-राजमंदी-रायनपाड़ खंड का निरीक्षण किया

हेदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र रत्न)। महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे संजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को विजयवाड़ा मंडल के तृती-राजमुंदरी-रायनपाड़ा खंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ विजयवाड़ा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मोहित सोनकिया और मुख्यालय एवं मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

संजय कुमार श्रीवास्तव ने विजयवाड़ा मंडल के तुनी-राजमुंदरी-गोदावरी-कोन्वर-निंदादावोलु-एलुरु-रायनपाडु खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खंड में रेलवे पटरियों के रखरखाव और पुलों एवं सिम्रलिंग प्रणालियों के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने

जा रही सूखा सावधानियों का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने कार्यों की प्रगति की सहजाना की और मंडल अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने की सलाह दी ताकि परिषोजनाओं को निर्धारित तिथियों तक पूरा किया जा सके। महाप्रबंधक ने कोव्चुर रेलवे स्टेशन का भी विस्तृत निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने स्टेशन के यात्री सुविधाओं, सुविधाओं और परिचालित क्षेत्र की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान, महाप्रबंधक ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उन्हें विभिन्न परिषोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। कई प्रतिनिधियों ने भी महाप्रबंधक से मुलाकात की और क्षेत्र से संबंधित रेल विकास योजनाओं के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

कालेश्वरम परियोजना पर घोष आयोग की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित : बीआरएस

आयोग की रिपोर्ट पर सिंचाई मंत्री की दायें पर उठाय़ा सवाल
हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र बीएन)। कालेश्वरम परियोजना पर घोष आयोग की रिपोर्ट को लेकर वीआएस नेताओं ने काँग्रेस सरकार पर पण्डितवा करते हुए उस पर राजनितिक लाभ के लिए संस्थाओं को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट पर सिंचाई मंत्री एन उमरा कुमार रेड्डी के दायें पर सवाल उठाते हुए उनके कानूनी जान पर सवाल उठाया है। पूर्व मंत्री निर्मल जेन्सुन रेड्डी ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त जांच आयोग न्यायिक निकाय नहीं हैं और वे अदालतों की तरह फैसले नहीं दे सकते।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीति फायदे के लिए चुनौती को तोड़-मोड़ रही है। उन्होंने सरकार पर 665 पत्रों की रिपोर्ट के तथ्यों हिस्सों को लौकिक बनाने और बीआरएस और उसके नेता के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाने के लिए उसे घटाकर 60 पत्रों का करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आयोग, जिसने चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्रियों टी हरीश राव और एटलार राजेंद्र तथा कुछ अधिकारियों को दोषी पाया, ने परियोजना निर्माण में विभिन्न चरणों में शामिल अन्य लोगों को क्यों छोड़ दिया। विधान परिषद में बिश्म के नेता एस मधुसूदन चारी ने कहा कि कांग्रेस में संस्थागत ईमानदारी की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि आपाकाल से लेकर चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने तक, कांग्रेस ने संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की और अब घोष आयोग की रिपोर्ट का राजनीतिकरण कर रही है। बीआरएस नेता जी देवी प्रसाद ने रिपोर्ट से मनमाने ढंग से विषयवस्तु चुनने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और उन्हें हरीश राव के हालिया विस्तृत खंडन का जवाब आमंत्रित प्रस्तुति से देने की चुनौती दी। उन्होंने दलबद्ध विरोधी फैसलों पर रेवंत रेड्डी की पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दोहरे मापदंड की आलोचना की, जिसमें उन्होंने बीआरएस को निशाना बनाया, जबकि उसी रिपोर्ट में नामित अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों को बचाया।

तेलंगाना में अनोखे ढंग से साइबर जागरूकता दिवस का हुआ आयोजन

एक ही दिन में 577 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित रचा इतिहास

हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र चर्चा)। तेलंगना साइबर सुरक्षा क्वार्टरों (टीजीसीएसबी) ने तेलंगना की सभी पुलिस इकाइयों के सहयोग से बुधवार को एक अभिनव और सफल तरीके से साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया। इसके तहत, राज्य भर के विविध स्कूलों और कॉलेजों में 577 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें हजारों छात्रों और शिक्षाविदों ने साइबर सुरक्षा पर सार्वक चर्चा की। साइबर

सुरक्षा पर प्रमुख विषयों पर जागरूकता के लिए प्रत्येक पविलियन में इकाई ने अपने अधिकांश क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से महत्वपूर्ण विषयों पर इंटीक्टिव जागरूकता सत्र आयोजित किए। इनमें व्यावसायिक और निवेशकों, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, ऋण धोखाधड़ी, विज्ञापन धोखाधड़ी और ऑनलाइन सुरक्षा तकनीकों शामिल थे। छात्रों द्वारा रचनात्मक गतिविधियों में छात्रों को साइबर सुरक्षा ज्ञान

सिखाने को और अधिक रोचक बनाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, साइबर अपराध विषयों पर लघु नाटक, 2 मिनट की जागरूकता रील पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन गतिविधियों ने छात्रों को साइबर अपराध को समझने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया। सीसीपीएस और स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारियों ने अतिथि वक्ता और

निर्णायक के रूप में भाग लिया और टीजीसीएसबी द्वारा तैयार सामग्री पर आधारित जागरूकता सत्र दिए। भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र देने के बाद, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान ने एक "साइबर मुक्त दीवार" स्थापित की।

भारत
ICAR

भारत अनुप-केन्द्रीय चारा
ICAR - Central Research Institute
संशोधन,
पटना-800 014
Ph : (65) 24303161, 24303165, 243144
www.icar-cri.com, www.cri.res.in

पूर्य नत रेलवे

निविदा सूचना क्र. WAT-TRS-OT-09-
2025-26

रक्षा वस्त्र कर्षण का काम : RSDO रुनागन जैठ
RSDSO पटवड/EL/M54045 Rev 9/07 निष्का
29.04.2016 के अनुसार लोकोस (Locos) में श्रेय से
भरा तब संगीतल CEC कवर के अतः कर्मि
अधिकांश का रुनागन/परिवहन।

प्रति मीटर (दूरी) में : 7,71,502.61 रु.
कमी में : 15,400/- , कारा पूरा होने की अवधि : 06
महीने।

निष्का बत होने को तिदि च समय उ निष्का:
25.08.2025 तक ही 1500 बजे।

निविदा प्रत्येकज से संघीया भुगतान विवरण
संगीतल www.freps.gov.in में अध्यासी होने।

वरिष्ठ माइल विस्तृत अभियाना (TRS),
WAT-43A/QJ/25-26 वाणिचर

महिला अधिकारी से यौन शोषण के आरोप में मथुरा के उपायुक्त सहित सात अधिकारी सस्पेंड

लखनऊ, 6 अगस्त (एजेंसियां)। यौन शोषण के आरोप में राज्य कर विभाग में मथुरा में तैनात डिप्टी कमिश्नर कमलेश कुमार पंडेय सहित सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। शेष छह सदस्य आंतरिक परिवाद समिति (विशाखा) के सदस्य हैं, जिन पर आरोपी डिप्टी कमिश्नर को बचाने के आरोप हैं। मंगलवार देर शाम सभी का निलंबन आदेश संयुक्त सचिव रघुवीर प्रसाद ने जारी कर दिया। राज्यकर विभाग में यौन उत्पीड़न के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई है। कमलेश कुमार पंडेय राज्य कर विभाग मथुरा खंड एक में तैनात हैं। उनकी अधीनस्थ महिला अधिकारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये भी आरोप लगाए कि कई अवसरों पर उन्होंने अनैतिक व्यवहार किया। शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। इस पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के अंतर्गत निलंबित करके संयुक्त आयुक्त बांदा कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

मिर्जापुर में लाल निशान के पार हुई गंगा, 14 की मौत

मिर्जापुर, 6 अगस्त (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मिर्जापुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां उफनाई गंगा वर्ष 2021 के अपने उच्चतम जलस्तर से चुनाव में सात और नरायणपुर में 18 सेमी ऊपर बह रही है। सिंचाई विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। गंधा, बारिश से हुए हादसों में 14 की जान चली गई। चुनाव क्षेत्र में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। 2021 में यहां का जलस्तर खतरे के निशान यानी लाल निशान 75.28 मीटर से ऊपर पहुंच गया था। मंगलवार को इससे भी सात सेमी ज्यादा हो गया। इससे 36 गांव प्रभावित हैं। यहीं के नरायणपुर में स्थिति और भी खराब है।

बदमाशों को पकड़ने से कैसे मशहूर हो गई रेलवे पुलिस

गाजियाबाद, 6 अगस्त (एजेंसियां)। रामपुर का चाकू देश-दुनिया में मशहूर है, लेकिन गाजियाबाद जीआरपी चाकू के साथ बदमाशों को पकड़ने में मशहूर हो गई है। जीआरपी ने पिछले सात माह में चाकू के साथ 59 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें चौकाने वाली बात ये है कि इनमें से 58 बदमाशों से बरामद 58 चाकूओं का साइज, आकार, लंबाई व चौड़ाई सब एक समान है। गाजियाबाद जीआरपी ने जनवरी से जुलाई तक 319 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 205 एफआईआर यात्रियों ने चोरी सहित अन्य धारा में दर्ज कराई हैं। जबकि विभिन्न आरोपों में पकड़े गए 114 लोगों के खिलाफ जीआरपी की ओर एफआईआर दर्ज की गई हैं। जीआरपी की ओर से दर्ज 114 में से 59 एफआईआर चाकू के साथ गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ हैं। इस वर्ष जीआरपी ने रिकॉर्ड चाकू बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जीआरपी के मालखाने में बरामद 200 से अधिक चाकू एकत्रित हो गए हैं।

पति के सामने पत्नी ने जान दी

कानपुर, 6 अगस्त (एजेंसियां)। कानपुर में पति के सामने पत्नी ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पत्नी गुस्से से कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पति बाहर से दरवाजा खटखटाता रहा। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो पति घबरा गया। उसने खिड़की से देखा तो पत्नी पंखे से फंदा लगा रही थी। वह चीखने लगा। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ा पाया। वह करीब 20 मिनट तक खिड़की पर हाथ-पैर मारता रहा। पत्नी को सुसाइड न करने की दुहाई देता रहा। लेकिन गुस्से में उसने पति की बात नहीं मानी और फंदे से लटक गई। पति के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के समय घर पर पति अकेला था। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

दो बच्चों को गंगा में फेंकने वाले दुर्गा सोनकर ने कबूला जुर्म

वाराणसी, 6 अगस्त (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपने दो नाबालिक बच्चो को गंगा में फेककर खुद भी गंगा में कूद गया। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि हत्या की नियत से ही दुर्गा दो दिन पहले अपने दोनों बच्चों के साथ रिंग रोड फेज 3 के गंगा पुल पर पहुंचा था। पहले उसने छोटे बेटे आशीष जिसकी उम्र 5 साल थी और फिर बड़े बेटे संदीप जिसकी उम्र 7 साल थी को गंगा में फेककर खुद भी पुल से कूद गया। दुर्गा सोनकर को लोगों ने बचा लिया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तबियत ठीक होते ही वह जिला अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिलट बाजार में फिर से उसकी गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार में 65 लाख लोगों के हटे नाम

एडीआर ने चुनाव आयोग से मांगी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में मामला



की सूची दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन पर चुनाव आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। **सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?**

वकील भूषण ने कहा जिन लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ने इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक वोटर को आवश्यक जानकारी मिले। शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण

को उस पर विचार करने दें, फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं। वकील भूषण ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम छूटे हुए बताए गए हैं। लेकिन उन 65 लाख नामों की कोई सूची नहीं दी गई है और कहा गया है कि 32 लाख लोग पलायन कर गए हैं और कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है। उन्हें यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं, कौन पलायन कर गया है और कौन मर चुका है। जाहिर है कि बीएलओ

अचानक मुख्यमंत्री पर उमड़ा चिराग पासवान का प्यार

पटना, 6 अगस्त (एजेंसियां)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में विपक्षी दलों पर राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उनके पिछले बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके एनडीए में दरार डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जुलाई में चिराग पासवान ने कहा था कि उन्हें बिहार में उस सरकार का समर्थन करने पर दुख हो रहा है, जो कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर इस तरह विफल हो रही है। उनका यह बयान 24 जुलाई को बोधगया में बिहार सैन्य पुलिस की एक अभ्यर्थी के साथ सामूहिक बलात्कार और बिहार में हाल ही में हुए हिंसक अपराधों के मद्देनजर आया था। चिराग पासवान ने स्पष्ट



किया कि उनकी टिप्पणी एक जनप्रतिनिधि और सत्तारूढ़ गठबंधन में एक सहयोगी के रूप में थी। मैं जनता के मुहों को जनता के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। चिराग पासवान ने दावा किया कि इस बार चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनेगी। हम 225 से अधिक सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हम साथ-साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ और मुझे अपने विचार रखने के

लिए वह मंच मिला है। चिराग ने कहा कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए जब मुझे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो बिहारियों की समस्याओं को बढ़ाते हैं, जैसे कानून और व्यवस्था का मुद्दा, तो मैं इसे सरकार के सामने मजबूती से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा, मुझे नीतीश कुमार और उनके शासन पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष मेरे शब्दों के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर जनता में भ्रम पैदा करने के लिए उनके बयानों की गलत व्याख्या कर रहा है। विपक्ष मेरे शब्दों को बढ़ा-चढ़ाकर हमारे बीच दरार दिखाने की पूरी कोशिश करता है।

‘4-4 बॉयफ्रेंड रखने वाली लड़कियां घर नहीं बसा सकती’, साध्वी प्राची बोलीं



मुजफ्फरनगर, 6 अगस्त (एजेंसियां)। प्रेमानंद जी महाराज और दीदी मां ऋतंभरा ने जो कहा, वह सही है। इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई लड़की चार-पांच बॉयफ्रेंड रखेगी, तो आगे चलकर उसका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल पाएगा। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर के समान माना गया है। मेरठ की घटना सबने देखी, जिसमें एक महिला ने अपने पति के टुकड़े करके डम में छुपा दिया। गैर मर्दों के चक्कर में पत्नियां ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। मुस्कान और रघुवंशी जैसे मामलों

में भी यही दिखता है कि कई बॉयफ्रेंड रखने की सोच का बुरा नतीजा होता है। ये बातें साध्वी प्राची ने मुजफ्फरनगर में कहीं। मुजफ्फरनगर में शिवमूर्ति मंदिर में दर्शन के बाद साध्वी प्राची ने आजकल की लड़कियों के चरित्र, सोशल मीडिया और तथाकथित धर्मांतरण मामलों पर बात की। उन्होंने कहा,सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लड़कियों ने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड किए, ताकि वे पैसा कमा सकें। हाईवे पर बनाई गई इन रीप्स पूरी दुनिया ने देखी। यह हमारी संस्कृति और आस्था दोनों का अपमान है। ऐसी हरकतें शर्मनाक हैं और यह खुलेआम अश्लीलता फैलाने जैसा है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर इस तरह की अश्लील चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ लड़कियां सिर्फ पैसे के लालच में ऐसा कंटेंट बना रही हैं, जो समाज पर बुरा असर डाल रहा है।

'कार्यालय से बाहर जाइए': सांसद इकरा हसन से अभद्रता मामले की जांच पूरी



सहारनपुर, 6 अगस्त (एजेंसियां)। कैराना सांसद इकरा हसन की तरफ से फरवरी माह में की गई सदर तहसील के तत्कालीन एसडीएम की शिकायत के मामले में जांच पूरी हो गई है। जांच में एसडीएम की तरफ से अवैध कब्जे की कार्रवाई को निष्पक्ष बताते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई। अभद्रता का मामला भी साबित नहीं हो सका। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद मंडलायुक्त की तरफ से सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। वहीं, सांसद इकरा हसन ने पिछले

एआईएमआईएम के इस नेता की जवा होगी संपत्ति



पटना, 6 अगस्त (एजेंसियां)। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता रहीमुद्दीन उर्फ हैबर की अवैध संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी। अभी तक रहीमुद्दीन किशनगंज के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन मामला सामने आने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव (2025) से पहले पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल पुलिस ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जिले के ऐसे पांच लोगों को चिह्नित भी किया गया जिन्होंने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति को बना लिया है। पांच नामों की सूची को पुलिस मुख्यालय को पूर्व में ही भेजा गया था। अब अपराध से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्ताव में नशे के सौदागर, देह व्यापार के दलाल और सरकारी रुपयों का गवन करने वाले व्यक्तियों का नाम शामिल है।

संभल हिंसा के आरोपी जफर अली समेत 60 समर्थकों पर केस दर्ज



संभल, 6 अगस्त (एजेंसियां)। हिंसा के आरोपी और जामा मस्जिद के सदर जफर अली एक बार फिर फस गए हैं। दरअसल हाल ही में जफर अली को कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह का जुलूस उनके समर्थकों ने निकाला, उससे सभी हैरान रह गए। दरअसल 1 अगस्त के दिन जफर अली जेल से रिहा हुए। इसके बाद वह कार का सनरूप खोलकर खड़े हो गए और फिर काफिले के साथ उनका जुलूस निकाला गया। वह जुलूस के साथ ही संभल पहुंचे। इस दौरान सड़कों पर जमकर नारेबाजी की गई और आतिशबाजी की गई। अब पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है। बता दें कि संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन सभी को निषेधज्ञा उल्लंघन का आरोपी बनाया है।

2 बच्चों की मां ने भांजे से रखाई शादी, पति को छोड़कर हुई फरार



बांका, 6 अगस्त (एजेंसियां)। बिहार के बांका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की मां ने अपने भांजे से शादी रचाई है और पति को छोड़कर फरार हो गई। इस मामले के सामने आने के बाद इलाकों में चर्चाओं का बाजार गरम है। रघुनाथपुर गांव निवासी शिवम कुमार की पत्नी पूनम कुमारी ने अपने ही भांजे से प्रेम संबंध बनाकर पति और दो बच्चों को छोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार, शिवम की शादी वर्ष 2014 में अमरपुर के दिग्धी पोखर निवासी भागीरथ साह की पुत्री पूनम कुमारी से हुई थी। विवाह के बाद दोनों को दो बेटे हुए, जिसमें एक की उम्र 10 साल और दूसरे की उम्र 8 साल है। कुछ समय पहले से पूनम के दूर के रिश्ते में लगने वाले अंकित कुमार, जो गोपरी जमालपुर थाना क्षेत्र के भुरिया दियारा गांव का निवासी है, का उनके घर आना-जाना शुरू हुआ। धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध गहरे हो गए। दो दिन पहले पूनम अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़ कर चली गई। रात पूनम ने पति को फोन कर बताया कि उसने अंकित कुमार से मर्चाओं में शादी कर ली है और उसकी तस्वीरें भी भेज दीं। इस घटना से आहत पति शिवम कुमार ने अमरपुर थाने में आवेदन देकर अपने बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई है।

प्रतापगढ़ में फिर मुठभेड़ तीन बदमाश गिरफ्तार

प्रतापगढ़, 6 अगस्त (एजेंसियां)। जिले में एक बार फिर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। रात संग्रामगढ़ के बाद बुधवार भोर फतनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चोरी और लूट के तीन अंतर्जनपदीय आरोपित पकड़े गए। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है। फतनपुर के छानापार नहर पुलिस के पास फतनपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ खुद्वी सराय दली कोतवाली नगर के पैर में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। इसके अलावा उसके दो और साथी भी पकड़े गए। घायल को सीएचसी गौरा के बाद राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा गया है।

डिप्टी सीएम ने मधिरा निर्वाचन क्षेत्र में दो औद्योगिक पार्कों के लिए वित्तीय सहायता मांगी

भट्टी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की



नई दिल्ली, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने केंद्र सरकार से मधिरा निर्वाचन क्षेत्र में दो औद्योगिक पार्कों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू, समाज कल्याण मंत्री अदलुपी लक्ष्मण और सांसद मल्लू रवि के साथ बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी से मुलाकात की और इस संबंध में औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार की ओर से, खम्मम जिले के येंडापल्ली (मधिरा मंडल) और रैमिदिचेरला (एरुपलेम मंडल) में एमएसएमई पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन पार्कों को क्रमशः 85 एकड़ और 60 एकड़ में विकसित करने की योजनाएँ तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (हैदराबाद-विजयवाड़ा कॉरिडोर) के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और आस-पास के कस्बों, रेलवे नेटवर्क और बंदरगाहों से इनकी उत्कृष्ट

कनेक्टिविटी है। इन पार्कों के विकास से स्थानीय युवाओं, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदायों के युवाओं को औद्योगिक अवसर प्राप्त होंगे। भट्टी ने कहा कि इन पार्कों को विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और इनसे कम से कम 5,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

तेलंगाना सरकार ने इन पार्कों के विकास हेतु वित्तीय सहायता हेतु एमएसएमई-सीडीपी (क्लस्टर विकास कार्यक्रम) के तहत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु केंद्र से पूर्व अनुमोदन मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठा रही है और उसने राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दो नए एमएसएमई पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। एमएसएमई क्षेत्र समावेशी आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक बन रहा है। भट्टी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित एमएसएमई पार्क, यही राज्य सरकार का व्यापक दृष्टिकोण है।

बैठक के दौरान, मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि तेलंगाना एमएसएमई-सीडीपी योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा है। तेलंगाना सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक प्रतिष्ठित योजना का मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एमएसएमई पार्क स्थापित करना है।

भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि इन पार्कों में छोटे-छोटे फ्लैट वाले फ़ैक्टरी परिसर होंगे और ये छोटी औद्योगिक इकाइयों को सहयोग देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेंगे, जिससे एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। वर्तमान में, एमएसएमई-सीडीपी योजना के तहत, तेलंगाना सरकार केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से 25 परियोजनाओं को पहले ही क्रियान्वित कर रही है। इन प्रगतिशील पहलों के माध्यम से, उपमुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरेगा।

सट्टेबाजी ऐप मामले में विजय देवरकोंडा ईडी के समक्ष हुए पेश

हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा बुधवार को सट्टेबाजी ऐप मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।

ईडी, जिसने हाल ही में सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने वाली फिल्मी हस्तियों को नोटिस जारी किया था, ने विजय को भी नोटिस भेजकर उन्हें बशौरबाग स्थित ईडी जोनल कार्यालय में जांच टीम के समक्ष पेश होने को कहा है। ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान फिल्म अभिनेता से उनके वित्तीय लेनदेन और बैंक विवरण के बारे में पूछताछ किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि अभिनेता, जिन्होंने पहले एक सट्टेबाजी ऐप से संबंधित विज्ञापन में काम किया था, पर साइबरबाद पुलिस ने अन्य लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। ईडी ने एकआईआर के आधार पर मामले



की समानांतर जांच शुरू की थी। आरोप है कि फिल्मी हस्तियों द्वारा सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से कई लोग आकर्षित हुए और उन्हें भारी

वित्तीय नुकसान हुआ, यहां तक कि कुछ लोगों ने अपनी जान भी ले ली। ईडी अब तक 36 फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेज चुका है। राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालाँकि, उन्होंने 11 अगस्त को फिर से पेश होने की अनुमति मांगी थी। ईडी ने मंचू लक्ष्मी को भी 13 अगस्त को जांच के लिए पेश होने का नोटिस भेजा है। वरिष्ठ अभिनेता प्रकाश राज

पहले ही 30 जुलाई को ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए थे और मामले के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया था।

एसटी आवासीय छात्रावास पर एसीबी का छापा

कल्याण अधिकारी हिरासत में संगारेड्डी, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने बुधवार को नरसापुर मंडल के मोहम्मदाबाद स्थित एसटी आवासीय छात्रावास में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई छात्रावास कल्याण अधिकारी रेखा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद की गई, जिन्हें एसीबी ने हिरासत में ले लिया था। एसीबी के डीएसपी मेदक के सुदर्शन ने कहा कि तलाशी अभियान जारी रहेगा।

सिलेंडर लीक से परिवार के तीन सदस्य झुलसे

इंदिरम्मा का घर न मिलने पर एक व्यक्ति ने दी आत्मदाह की धमकी



सिद्दीपेट, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। इंदिराम्मा आवास के आवंटन में अनियमितताएँ बुधवार को फिर सामने आईं, जब नागनूर मंडल के पलामकुला गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अंतिम समय में मकान देने से इनकार

किए जाने पर आत्मदाह का प्रयास किया।

श्रीकांत नाम का यह व्यक्ति व्वस्त सिद्दीपेट-हनमकोंडा रोड पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके सड़क पर बैठ गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पेट्रोल

से भरी बोतल लिए हुए, उसने खुद को आग लगाने की धमकी दी और स्थानीय इंदिराम्मा आवास समिति, जिसमें कांग्रेसी नेता शामिल हैं, पर जानबूझकर उसे लाभार्थियों की सूची से बाहर करने का आरोप लगाया।

श्रीकांत ने कहा कि उन्हें शुरू में आवास योजना के लिए चुना गया था, लेकिन निहित स्वार्थ के चलते अंतिम चरण में उनका नाम हटा दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पात्रता मानदंड पूरे करने के बावजूद, समिति ने मनमाने ढंग से उन्हें आवंटन देने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोग और अधिकारी मौके पर पहुंचे और श्रीकांत को यह कदम उठाने से रोका। उन्होंने उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली और मामला बिगड़ने से पहले उसे शांत किया।

बीआरएस ने बनकाचेरला परियोजना पर राज्यसभा में पेश किया स्थगन प्रस्ताव

हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस पार्टी ने बुधवार को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की जा रही विवादास्पद गोदावरी-बनकाचेरला परियोजना पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। पार्टी ने कहा कि यह परियोजना तेलंगाना के वाजिब हिस्से के पानी को हटा देगी और राज्य के किसानों के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। बीआरएस संसदीय दल के नेता के.आर. सुरेश रेड्डी और सांसद दिवाकोंडा दामोदर राव ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को नोटिस देकर आग्रह किया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियमित कार्यावाही रोक दी जाए। हालाँकि, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

बीआरएस सांसदों ने कहा कि गोदावरी बेसिन पर बनाई जा रही यह परियोजना अंतर-राज्यीय जल-बंटवारे के मानदंडों का उल्लंघन करती है और तेलंगाना की जल सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

दिल्ली धरना बीसी अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि महज़ राजनीतिक प्रदर्शन : डॉ. वकुलाभरणम

तेलंगाना बीसी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ने उठाए सवाल



हैदराबाद, 6 अगस्त (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना बीसी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. वकुलाभरणम कृष्णमोहन राव ने बुधवार को सोमाजीगुड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली धरना बीसी अधिकारों की लड़ाई नहीं बल्कि महज़ राजनीतिक प्रदर्शन है।

उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास वास्तविक नीयत होती तो वह विशेष रूप से याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से लंबित विधेयकों पर त्वरित निर्णय का रास्ता निकाल सकती थी। कानूनी रास्ता मौजूद होते हुए भी ऐसे नाटक क्यों? यह बीसी अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं बल्कि पार्टी उच्च नेतृत्व की नजरों में आने का पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में तमिलनाडु फैसले के संदर्भ में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, जिससे साफ है कि

कानूनी उपाय का रास्ता खुला हुआ है। फिर भी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय जंतर-मंतर पर धरना देना चुना, जो जनता को गुमराह करने वाला राजनीतिक नाटक है।

उन्होंने सरकार के दोहरे खेये पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण लागू करने के लिए बूसानी डेडिफ़ेड कमीशन की रिपोर्ट पर्याप्त थी तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने उसे प्राप्त करने के लिए समय क्यों नहीं निकाला? आखिरकार बूसानी कमीशन को अपनी रिपोर्ट बिना प्रचार के मुख्य सचिव को सौंपनी पड़ी। लेकिन जब जस्टिस सुधर्शन रेड्डी वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट सौंपी तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कई मंत्री उसे लेने एमसीआरएचआरडी तक गए। बूसानी कमीशन और जस्टिस रेड्डी समिति के साथ यह भेदभाव क्यों? यह खेत सरकार के

बीसी विरोधी खेये का साफ संकेत है। डॉ. वकुलाभरणम ने कहा, कालेश्वरम परियोजना की तथाकथित "व्यापक अध्ययन" रिपोर्ट तैयार करने में 16 महीने लगाए गए, लेकिन करोड़ों बीसी के भविष्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी कर दी गई। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए नियुक्त आयोगों को समुचित समय तक नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, बूसानी कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए मात्र एक माह की समयसीमा दी गई, जो सरकार के आदेश जीओ No.49 में स्पष्ट है।

क्या ये रिपोर्ट बिना व्यापक अध्ययन के पेश की गई? ये रिपोर्ट कहाँ हैं? इन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? कालेश्वरम रिपोर्ट तो तत्काल जारी कर दी गई, लेकिन करोड़ों बीसी के जीवन से जुड़े अहम दस्तावेज क्यों छुपाए जा रहे हैं? जातिवार सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? जस्टिस सुधर्शन रेड्डी समिति की

रिपोर्ट कहाँ है? इन आयोगों की कानूनी वैधता क्या है? ये सब दिखाता है कि बीसी आरक्षण के नाम पर वास्तविक कदमों से ज्यादा राजनीतिक नाटक और दिखावा किया जा रहा है। करोड़ों की उम्मीदों और अधिकारों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे में सरकार की यह लापरवाही अक्षम्य है। दिल्ली धरने पर उन्होंने टिप्पणी की, यह सिर्फ एआईसीसी का ध्यान खींचने के लिए किया गया पीआर अभ्यास था। बीसी आरक्षण की असली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, न कि खेत रेड्डी के दिल्ली प्रेजेंटेशन या मंचित धरनों से। बीसी के लिए वास्तविक न्याय केवल अदालतों से मिलेगा, राजनीतिक नाटकों से नहीं। इस अवसर पर राज्य बीसी एक्च वेटिका के अध्यक्ष नरसिंह यादव, राष्ट्रीय बीसी अध्ययन मंच के संयोजक एम. मारुति प्रसाद और राज्य बीसी नेता अम्बट्टी सुधाकर, रमेश आदि उपस्थित रहे।